विडंबना मानसून के दौरान लाखों रूपए खर्च कर हर वर्ष किया जाता है पौधरोपण, रखरखाव के अभाव में पेड़ नहीं बन पा रहे पौधे

कागजों में हरियाली, हकीकत में जमीन खाली

नवभारत, कटनी। जिले में हर वर्ष मानसून के दौरान बड़े पैमाने पर पौधारोपण अभियान चलाया जाता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 12 वर्षों में 1 करोड़ 1 लाख 70 हजार 817 पौधे लगाने का दावा किया गया है। लेकिन शहर और जिले की वर्तमान हरियाली इन दावों की सही साबित करते नजर नहीं आ रही है। शहर की मुख्य सड़कों के कई डिवाइडरों हरियाली कम ही नजर आती है। एनकेजे क्षेत्र के रोशननगर स्थित अटल निकुंज में कोरोना काल से पहले बड़े स्तर पर पौधारोपण किया गया था, उनमें से अधिकांश पौधे रखरखाव के आभाव में सूख गए हैं, दो वर्ष पहले भी वहां दोबारा पौधे लगाए गए, बावजूद इसके क्षेत्र पूरी तरह विकसित हरित पट्टी का रूप नहीं ले सका। इसी तरह उमरियापान के पास करौंदी स्थित भारत के भौगोलिक केंद्र को हरित पर्यटन

स्थल बनाने की योजना भी अधूरी नजर आ रही है, जहां लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद पर्याप्त हरियाली विकसित नहीं हो सकी। वन विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार वर्ष 2016 में 4 लाख 14 हजार 427, 2017 में 5 लाख 53 हजार 829, 2018 में 9 लाख 48 हजार 9, 2019 में 6 लाख 37 हजार 50, 2020 में 1 लाख 80 हजार, 2021 में 95 हजार 800, 2022 में 10 लाख 56 हजार 55, 2023 में 8 लाख 91 हजार 90, 2024 में 11 लाख 6 हजार 955, 2025 में 13 लाख 90 हजार 530, 2026 में 15 लाख 6 हजार 542 और 2027 में 13 लाख 90 हजार 530 पौधे लगाने का लक्ष्य और उपलब्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2016 से 2027 तक लगभग 1 करोड़ 1 लाख 70 हजार 817 पौधे लगाने का लक्ष्य और उपलब्धि दर्ज की गई है। हर साल इस अभियान पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन शहर और जिले की मौजूदा स्थिति इन आंकड़ों पर सवाल खड़े कर रही है। पर्यावरणविदों का कहना है कि पौधारोपण की संख्या नहीं, बल्कि पौधों के जीवित रहने की दर सफलता का पैमाना होनी चाहिए। उनका सुझाव है कि हर पौधे की जियो-टैगिंग, नियमित सिंचाई, सुरक्षा और कम से कम तीन से पांच वर्ष तक रखरखाव किया जाए। उनका मानना है कि ऐसा नहीं होने पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च कर लगाए गए पौधे सिर्फ सरकारी फाइलों में फलेंगे-फूलेंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि लगाए गए अधिकांश पौधे पेड़ बन पाते तो शहर में धूल कम होती, तापमान घटता, भूजल संरक्षण बेहतर होता और पर्यावरण संतुलन मजबूत होता। एक विकसित पेड़ ऑक्सीजन, तापमान नियंत्रण, वर्षा जल संरक्षण और जैव विविधता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पर्यावरण से जुड़े लोगों का कहना है कि हर साल नए पौधे लगाने पर जोर दिया जाता है, लेकिन पहले लगाए गए पौधों का सर्वाइवल ऑडिट शायद ही सार्वजनिक होता है। उनका अनुमान है कि लगाए गए पौधों में से सिर्फ 20 से 25 प्रतिशत ही पेड़ बनने तक पहुंच पाते हैं। गुलवारा क्षेत्र में विकसित किए जा रहे नगर वन में हजारों पौधे लगाए गए, लेकिन आज भी वहां बड़े हिस्से में हरियाली कम और खाली जमीन ज्यादा दिखाई देती है। वहीं बस स्टैंड से चाका तक डिवाइडरों पर लगाए गए पौधे भी अधिकांश स्थानों से गायब हो गए हैं। कई स्थानों पर पौधे सूख गए, जबकि सुरक्षा के लिए लगाई गई रेलिंग भी क्षतिग्रस्त या चोरी हो गई। जानकारी के अनुसार जिले में इस वर्ष 13 लाख 90 हजार 530 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें करीब 60 प्रतिशत पौधारोपण पूरा कर दिया गया है।

लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है पुलिस की कार्रवाई

पुरानी कचहरी चौक में समाजवादी पार्टी ने किया विरोध प्रदर्शन

नवभारत, कटनी। दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों पर हुए कथित पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में गुरुवार को समाजवादी पार्टी और समाजसेवियों ने सांकेतिक धरना-प्रदर्शन किया। पुरानी कचहरी चौक स्थित वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा के सामने आयोजित प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए छात्रों की मांगों पर संवाद के माध्यम से समाधान निकालने की मांग की। धरने के दौरान प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, अच्छी शिक्षा न दे सके जो, वह सरकार निकम्मी है और छात्रों पर अत्याचार नहीं सहेंगे जैसे नारे लगाए। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों और युवाओं की आवाज को बलपूर्वक दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने जंतर-मंतर पर हुई पुलिस कार्रवाई को लोकतांत्रिक मूल्यों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ बताया। समाजवादी पार्टी नेताओं ने सरकार से छात्रों की समस्याओं का जल्द समाधान निकालने और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करने वाले दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की।

प्रदर्शन में संदीप नायक, विन्देश्वरी पटेल, प्रभात पांडे, एडवोकेट हेमंत श्रीवास्तव, सचिन शर्मा, ओम आहूजा, मजहर नियाजी और विक्रम रजक सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। आयोजकों ने कहा कि फिलहाल यह सांकेतिक धरना है, लेकिन मांगें पूरी नहीं होने पर चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा।

एक नजर में

स्कूलों में लगाए जाएंगे विशेष आधार शिविर

नवभारत, बहोरीबंद। जिले के विभिन्न विकासखंडों में चिन्हित विद्यालयों में 27 जुलाई से विशेष आधार शिविर आयोजित किए जाएंगे। कलेक्टर आशीष तिवारी के निर्देशानुसार आयोजित होने वाले इन शिविरों में यू-डायस पोर्टल पर लंबित विद्यार्थियों के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट के साथ-साथ आम नागरिकों के आधार कार्ड में आवश्यक संशोधन और अद्यतन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। शिविरों में विशेष रूप से उन हितग्राहियों को लाभ मिलेगा, जिनका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक न होने के कारण विभिन्न योजनाओं की ई-केवाईसी प्रक्रिया लंबित है। ऐसे आवेदक अपने आधार में मोबाइल नंबर अपडेट कराकर योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए संबंधित रोजगार सहायकों, सचिवों और पटवारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। निर्धारित तिथियों पर सुबह 10 बजे से शिविर प्रारंभ होंगे। आधार केंद्र संचालकों को शासकीय मशीनों और आवश्यक उपकरणों के साथ उपस्थित होकर सेवाएं प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को विद्यार्थियों को आवश्यक दस्तावेजों सहित शिविरों में लाने तथा संबंधित कार्यालय प्रमुखों को सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

जलकर, बाजार शुल्क से आय बढ़ाएं ग्राम पंचायतें

पंचायतों को आर्थिक मजबूत बनाने दिया गया प्रशिक्षण

नवभारत, ढीमरखेड़ा। जिले की ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से आयोजित तीन दिवसीय ओएसआर वर्चुअल प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतिम दिन ढीमरखेड़ा जनपद पंचायत की ग्राम पंचायतों के सचिवों और ग्राम रोजगार सहायकों को प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान जिला पंचायत सीईओ हरसिमरनप्रीत कौर ने ऑनलाइन चर्चा करते हुए पंचायतों की आय बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतें सिर्फ शासकीय अनुदान पर निर्भर न रहें, बल्कि मध्यप्रदेश पंचायत राज और ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के प्रावधानों के

तहत जलकर, स्वच्छता कर, प्रकाश कर और बाजार शुल्क जैसे स्थानीय कर लगाकर अपनी आय बढ़ाएं। आर्थिक रूप से मजबूत होने पर पंचायतें स्थानीय समस्याओं का समाधान स्वयं कर सकेंगी। सीईओ ने कर वसूली का पारदर्शी हिसाब रखने और पोर्टल पर समयबद्ध डेटा प्रविष्टि करने के निर्देश दिए ताकि मॉनिटरिंग प्रक्रिया मजबूत हो सके। कार्यक्रम में आरजीएसए के नोडल अधिकारी पंकज नामदेव और मास्टर ट्रेनर सपन चतुर्वेदी ने प्रतिभागियों को ओएसआर की तकनीकी प्रक्रिया और डेटा एंट्री की जानकारी दी। इस दौरान ढीमरखेड़ा जनपद पंचायत के सीईओ युजवेंद्र कोरी, संबंधित अधिकारी और ग्राम पंचायतों के सचिव और ग्राम रोजगार सहायक मौजूद रहे।

अधूरे सड़क निर्माण ने बढ़ाया खतरा, नमी से आई मकान की दीवार में दरार

बरसात का पानी भरने से कमजोर हो रही दीवार

बरसात का पानी भरने से कमजोर हो रही दीवार

नवभारत, बाकल। बहोरीबंद जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत बाकल में अधूरे सीसी सड़क निर्माण और जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से स्थानीय रहवासियों के मकानों पर खतरा मंडराने लगा है। पटेल मोहल्ले में एक मकान की कच्ची दीवार में गहरी दरारें आ गई हैं और वह गिरने की स्थिति में पहुंच गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते आवश्यक कदम नहीं उठाए गए तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है।

रहवासियों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा पटेल मोहल्ले में सीसी सड़क का निर्माण कार्य शुरू कराया गया था, लेकिन इसे लंबे समय से अधूरा छोड़ दिया गया है।

बरसात के दौरान सड़क पर पानी भरने लगा, जिससे पानी आसपास के मकानों की नींव और दीवारों में समा गया। लगातार नमी रहने के कारण एक कच्चे मकान की दीवार दो हिस्सों में बंटती दिखाई दे रही है और उसके कभी भी ढहने की आशंका बनी हुई है। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि जिस मार्ग पर यह दीवार स्थित है, वहां से प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग आवागमन करते हैं।

यदि दीवार अचानक गिरती है तो राहगीरों के साथ गंभीर दुर्घटना हो सकती है। लोगों का आरोप है कि सड़क निर्माण के साथ नाली का निर्माण नहीं कराया गया, जिसके कारण वर्षा का पानी निकासी नहीं होने से मकानों के आसपास जमा हो रहा है और दीवारों में लगातार नमी बनी हुई है। रहवासियों ने प्रशासन और ग्राम पंचायत से मांग की है कि अधूरे निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा कराया जाए, जल निकासी के लिए नाली का निर्माण कराया जाए। साथ ही क्षतिग्रस्त मकान का तत्काल निरीक्षण कर आवश्यक सुरक्षा उपाय किए जाएं, ताकि किसी संभावित जनहानि को रोका जा सके।

अनुपूरक बजट में विजयराघवगढ़ विधानसभा को मिली दो पुलों की सौगात

कटनी नदी और महानदी में बनेंगे उच्च स्तरीय पुल

नवभारत, कटनी। मप्र विधानसभा के मानसून सत्र में प्रदेश शासन द्वारा रखें गए अनुपूरक बजट में विधायक संजय पाठक के प्रयासों से विजयराघवगढ़ विधानसभा को लगभग 40 करोड़ के दो उच्च स्तरीय पुलों सहित संपर्क मार्ग की सौगात मिली है। जानकारी के अनुसार भैंसवाही, घूंसुर को कांटी क्षेत्र से जोड़ने के लिए कटनी नदी पर ग्राम घुंसुर से ग्राम मोहास के बीच उच्च स्तरीय पुल के साथ ही 3 किलोमीटर की सड़क का निर्माण के साथ ही महानदी पर ग्राम बकेली से ग्राम गुड़ेहा, पिपरा को जोड़ने के लिए उच्च स्तरीय पुल के साथ ही 8.5 किलोमीटर की सड़क निर्माण की स्वीकृति अनुपूरक बजट में प्राप्त हुई है। इन पुलों के निर्माण के बाद किसानों और क्षेत्र वासियों को नदी के कारण अधिक दूरी तय करने में लगने वाला समय के साथ ईंधन की बचत होगी। विधायक ने मई माह में मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हुए पत्र के माध्यम से विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए कटनी और महानदी पर पुलों और पुलों को गांवों से जोड़ने के लिए सड़कों के निर्माण के प्रस्ताव दिए थे उन सभी प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने स्वीकार करते हुए तत्काल स्वीकृति दी गई थी अब अनुपूरक बजट में लगभग 40 करोड़ की लागत वाले कार्यों को बजटीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है। विजयराघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र को मिली इस उपलब्धी पर विधायक ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के विकास के विजन को पूरा करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री से क्षेत्र विकास के लिए जो भी मांगा गया है वह मिल रहा है।

पांच सूत्रीय मांगों को लेकर पटवारियों ने शुरू किया चरणबद्ध विरोध प्रदर्शन

पटवारी संघ ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन

नवभारत, उमरियापान। पांच सूत्रीय मांगों को लेकर पटवारी संघ ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीदार को ज्ञापन सौंपा है। जिन मांगों को लेकर पटवारी संघ द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है उनमें कैडर रिव्यू, पदोन्नति, समयमान वेतनमान तत्काल लागू किए जाने, नायब तहसीलदार विभागीय परीक्षा 2018 के बाद नहीं हुई, परीक्षा को जल्द कराए जाने, जज प्रोटेक्शन एक्ट में पटवारियों को भी शामिल किए जाए ताकि राजस्व प्रकरणों

में सीधे एफआईआर हो सके, स्वामित्व, संगणना, फार्मर आईडी आदि के रुके भुगतान तत्काल दिए जाने, संघ पदाधिकारियों के नियम विरुद्ध ट्रांसफर निरस्त करने और नियमित बैठकें कराने की मांग शामिल है। पटवारी संघ चरणबद्ध तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहा है। इससे पहले 15 से 17 जुलाई को 3 दिन सामूहिक अवकाश किया गया था, 20 से 23 जुलाई काली पट्टी बांधकर कार्य किया जा रहा है। 24 से 27 जुलाई तक शासकीय व्हाट्सएप समूहों का बहिष्कार किया जाएगा। 28 जुलाई से दो अगस्त तक ऑनलाइन कार्य वेबजीआईएस, सारा एप्प का बहिष्कार किया जाएगा। तीन अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी।

ज्ञापन सौंपने के दौरान कार्यकारणी जिला अध्यक्ष अशोक बागरी, पटवारी मनीष दहिया, महेंद्र थूल, अनिल सोनी, आनंद डेहरिया, लम्मू, सुधीर, आदेश, सुश्री जया, अजीत, कृष्ण, शशांक, नीरज, महेंद्र, अनेश सहित अन्य उपस्थित रहे।

जिला स्तरीय लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड की बैठक आज

नवभारत, कटनी। जिले में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के विकास, उद्योगों से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों एवं लंबित प्रकरणों की समीक्षा के लिए जिला स्तरीय लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड की बैठक कलेक्टर आशीष तिवारी अध्यक्षता में 24 जुलाई को शाम 4 बजे कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित की जाएगी। बैठक में बोर्ड के सदस्य और संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहेंगे। बैठक में सभी संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय पर पूरी जानकारी के साथ आने के लिए कहा गया है।

निरीक्षण कलेक्टर ने किया लमतरा औद्योगिक क्षेत्र और निमास मार्बल खदान का निरीक्षण

कटनी स्टोन सिर्फ एक खनिज नहीं है बल्कि जिले की विशिष्ट पहचान और विरासत है

नवभारत, कटनी। जिले के खनिज आधारित उद्योगों को नई पहचान दिलाने और स्थानीय स्तर पर निवेश और रोजगार के अवसरों का विस्तार करने की दिशा में कलेक्टर श्री आशीष तिवारी ने लमतरा औद्योगिक क्षेत्र और स्लीमनाबाद क्षेत्र के ग्राम निमास स्थित मार्बल खदान का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने उद्योगों की उत्पादन क्षमता, आधुनिक तकनीक, विपणन व्यवस्था और उद्यमियों के समक्ष आने वाली चुनौतियों की जानकारी लेकर संबंधित अधिकारियों को उनके निराकरण के निर्देश दिए। लमतरा औद्योगिक क्षेत्र में कलेक्टर ने एक जिला-एक उत्पाद के अंतर्गत कटनी सैंड स्टोन से तैयार

की जा रही कलात्मक मूर्तियों, आकर्षक नक्काशी और उत्कृष्ट शिल्पकृतियों का अवलोकन किया। उन्होंने आधुनिक गैंग सॉ, सीएनसी ऑटोमैटिक कार्विंग और स्टैच्यू कार्विंग मशीनों की कार्यप्रणाली देखी और युवा उद्योगपति अमन खरे से उत्पादन प्रक्रिया और बाजार की संभावनाओं पर चर्चा की। कलेक्टर ने कहा कि कटनी स्टोन सिर्फ एक खनिज नहीं, बल्कि जिले की विशिष्ट पहचान और विरासत है। इसकी गुणवत्ता और कलात्मक उपयोग को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार पर कटनी स्टोन से वॉल क्लैडिंग कराने की संभावना पर भी चर्चा की, ताकि स्थानीय उत्पादों को सरकारी परिसरों में भी प्रोत्साहन मिल सके। निरीक्षण के दौरान उप संचालक खनिज रत्नेश दीक्षित ने बताया कि जिले में वर्तमान में कटनी स्टोन की चार सक्रिय खदानें संचालित हैं। युवा उद्योगपति अमन खरे ने बताया कि उनकी इकाई को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 20 फीट ऊंची आदियोगी भगवान शिव की प्रतिमा निर्माण, राजस्थान के उदयपुर में स्लैब और टाइल्स निर्माण, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से भी महत्वपूर्ण कार्य प्राप्त हुए हैं। इससे कटनी स्टोन की गुणवत्ता और बढ़ती राष्ट्रीय मांग का पता चलता है। इसके बाद कलेक्टर ने ग्राम निमास स्थित मेसर्स बीडीएच इको एनर्जी इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई द्वारा संचालित मार्बल खदान, सोलर प्लांट का निरीक्षण किया। उन्होंने खदान संचालक प्रभाष कुमार राजगढ़िया से उत्पादन लागत, विपणन, गुणवत्ता और खनन से जुड़े व्यावसायिक पहलुओं पर चर्चा की। निरीक्षण के दौरान बताया गया कि निमास क्षेत्र का मार्बल अपनी मजबूती, टिकाऊपन और उत्कृष्ट गुणवत्ता के कारण उदयपुर, चित्तौड़गढ़ सहित देश के विभिन्न बाजारों में विशेष मांग रखता है। कलेक्टर ने कहा कि जिला प्रशासन उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने, स्थानीय खनिजों का मूल्य संवर्धन बढ़ाने तथा निवेशकों की समस्याओं के तत्काल समाधान के लिए प्रतिबद्ध है।